

[Shri Shivnath Singh]

Business in Lok Sabha, the Third Report the Rules Committee.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

TWELFTH REPORT

SHRI S. C. SAMANTA: (Tamiluk): I beg to present the Twelfth Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

SEVENTH REPORT

SHRI D. D. DESAI (Kaira): I beg to present the Seventh Report of the Committee on Government Assurances.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): With regard to the Report just presented, an assurance was given that every Report of the Commissioner for Scheduled Castes would be laid on the Table and discussed every year. That assurance has not been fulfilled. The Reports of the Commissioner for 1971-72 and 1972-73 have not been laid on the Table and not discussed. Even the Report for 1970-71...

MR. SPEAKER: Not like this. He had better write to me.

SHRI K. S. CHAVDA: The Committee should take note of assurances given by Government on the floor of the House.

13.07 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 17th December, 1973, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of the Konkan Passenger Ships (Acquisition) Bill, 1973.

3. Discussion and voting on:

(i) Demands for Excess Grants (General) for 1971-72;

(ii) Supplementary Demands for Grants (General) for 1973-74.

4. Consideration and passing of:

(i) The Income-Tax (Amendment) Bill, 1973.

(ii) The Water (Prevention and Control of Pollution) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

5. Consideration and passing of the following Bills on Tuesday, the 18th December, 1973:

(i) The Constitution (Thirty-third Amendment) Bill, 1973.

(ii) The Mulki Rules (Repeal) Bill 1973.

6. Consideration and passing of the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

7. Consideration and passing of the National Cooperative Development Corporation (Second Amendment) Bill, 1973.

8. Discussion on the International Situation.

श्री मधु लिमये (वांका) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में इन दिनों में, खाम कर कल जो घटना घटा है कि मैन्यु टैकम अमेंडमेंट आर्डिनैस के ऊपर बहस चल रही थी, कम्प्युनिस्ट पार्टी का अनुमोदन का प्रस्ताव था जो पाम हो गया . . .

अध्यक्ष महोदय : इस में वह कैसे आयेंगा ? हाउस के विजनेस के बरे में है । यह कैसे आयेंगा ?

श्री मधु लिमये : मैं अगले सप्ताह के कार्य पर ही बोल रहा हूँ आप को बताना रहा हूँ कि कितन रूप में चर्चा आ सकती है । आप कहेंगे तो दूसरी चीजों पर जाऊंगा । क्या आप बाद में उठाने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बाद में भी नहीं उठाने दे रहा हूँ । ऐसे कैसे आ सकता है । जो बिहार की बात है उस की चर्चा बिहार में कीजिए यहाँ क्या झगड़ा उठाते है । प्रदेश की बात यहाँ कैसे आएगी । इतना अधिक आप इसको न ले जाएँ । दुनिया भर को चीजे करने के लिए वक्ता कहां है हमारे पाम ?

श्री मधु लिमये : मैंने एक सबस्टैटिव मोशन की सूचना दी है नियम 184 के अन्तर्गत । मैं चाहता हूँ कि अगले सप्ताह में इस पर बहस करने का हम को मौका प्राप्त हो । क्या विषय है उसको मैं बताना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तरफ से कलीयरेंस होगी तभी तो आप बताएंगे

श्री मधु लिमये : मैं खड़ा हो जाता हूँ तो आप मुझे टोकने लगते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो दिया नहीं है . . .

श्री मधु लिमये : आज ही दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वही बिहार वाली बात है । मैंने इसको माना ही नहीं तो यह आएगी कैसे ।

श्री मधु लिमये : मैंने नोटिस दिया है मुझे आप कहने दीजिए ।

MR. SPEAKER: I have not allowed anything under rule 377 today. Only with respect to the statement, I allow.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begasari): Whether the Chair can be pleased to reject it—on that, I have to urge some points for your consideration.

श्री मधु लिमये : मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में लिखा हुआ है टैकमेशन के मामले में कि बिना चुने हुए सदस्य की स्वीकृति के सरकार चल नहीं सकती है । मैन्यु टैकम आर्डिनैस का मामला टैकमेशन का विषय है । उस पर सरकार हार पाई है । सरकार को इस्तीफा देना चाहिये । इस्तीफा नहीं देती तो गवर्नर को उसे हटाना चाहिये । गवर्नर यह नहीं कर रहा है, इसलिए गवर्नर को हटाने का . . . (इंटरप्लॉड)

MR. SPEAKER: That, I have not allowed.

सर्वा बोलिये मेरा क्या हरज है ? हो गया आपस में फैसला नहीं हुआ तो और बोल नोटिये । मैं बैठा रहता हूँ ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कहा है कि जो मोशन उन्होंने सुबह भेजा है मैं उसको एडमिट नहीं किया है ।

श्री मधु लिमये : अस्वीकार भी नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : किया है ।

श्री मधु लिमये : अगर अस्वीकार किया है तो इत्तिला देनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सुपर ह्यूमन हम तो है नहीं कि दस ग्यारह बजे आप मोशन लागू उसके बारे में इत्तिला आप को दे दे । जिस को एरुसैप्ट किया जाता है उसकी इत्तिला दे देते हैं ।

I am not bound to give information if it is rejected.

377 को भी आपने राइट बना लिया है ।

श्री मधु लिमये : 377 किस लिए है ? मैं डेढ़ दो मिन्ट मांग रहा हूँ और आप देने को तैयार नहीं हैं । लोक सभा में इस पर चर्चा नहीं होगी । एक वकील को दूसरी दलील से काटने की जगह हल्ला करने से मेरी दलील कटेगी नहीं ।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : ज्यादा दिन वहाँ सरकार चलेगी नहीं ।

एक माननीय सदस्य : चलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : किसी की चले, किसी की न चले, आप लोक सभा पर मेहरबानी रखिये । इसको आप चलने दीजिए । बिहार में किस की चलती है, किस की नहीं चलती है इसका बिहार ही जाने ।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): If this thing happened in Tamilnadu Assembly, what steps will you take? It is a question of the Constitution.

MR. SPEAKER: It is the same steps everywhere, even if it happens in Tamilnadu.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: If the Government fails? Do not try to shield this Government. They have butchered democracy.

श्री मधु लिमये : कौन सा मामला राज्य में उठना चाहिये और कौन सा लोक सभा में इसका मुझे पूरा पता है . . . (इंटरप्रॉज) यह क्या चल रहा है । आप शान्ति नहीं रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अधर में हो गई है, उधर स भी करवाइये ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के तहत राष्ट्रपति जी ने कमम खाई है कि वह संविधान की रक्षा करेंगे । राष्ट्रपति सारे काम मंत्रि-मंडल की मलाह पर करते हैं । मैं आप से यह जानना चाहता हूँ, और इस पर चर्चा करवाना चाहता हूँ, कि क्या बिहार में संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है । अनुच्छेद 164 (2) में कहा गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या उल्लंघन हुआ है ?

श्री मधु लिमये : आप ने कमेन्टरी शुरू कर दी है । अगर हम करेंगे, तो आप कहेंगे कि रनिंग कमेन्टरी करते हैं । मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ है और आप ने टोकना शुरू कर दिया है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर शान्ति नहीं होती है, तो आप सदन को स्थगित कर दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वहाँ की एसेम्बली चल रही है । वह इस पर एक्शन लेगी । जो कुछ करना है, वह करेंगी । क्या आप विधान सभा के झगड़े पार्लियामेंट में हल करेंगे ?

श्री मधु लिमये : राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करते हैं मंत्रि-मंडल की मलाह पर । (व्यवधान) राष्ट्रपति और केन्द्रीय मंत्रि-मंडल के क्या कर्तव्य हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राज्यों के झगड़े यहाँ हल न काजिए । इस बारे में बिहार की विधान सभा फैसला करेगी, पार्लियामेंट कैसे करेगी

श्री मधु लिमये : आप मुनना नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलाऊ नहीं किया है । मुनुं क्या ?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:
There are only two circumstances in which you might like to consider whether it is a matter for consideration by Parliament. I do not want to urge the consideration of the Emergency, because for all practical purposes, it is only a nominal Emergency, but even so, constitutionally Emergency is there.

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त अगले हफ्ते के विज़नेस की बात हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि उम में बिहार के बारे में डिमकशन को भी शामिल कर लिया जाये, तो कहिये। लेकिन इस मौके पर बिहार पर डिमकशन नहीं हो सकता है।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:
It is a matter primarily for the Bihar Assembly no doubt. But what has the Governor reported to the Central Government after the failure of the Government on this particular issue? We are entitled to know that. How are we to assure ourselves that the Ministry there does continue to enjoy the confidence of the legislature?

अध्यक्ष महोदय : जैसे श्री मधु लिमये इस मामले को हल करना चाहते हैं, वैसे काम नहीं चलेगा।

श्री मधु लिमये : आप ने मुझे सुना ही नहीं। आप ने कहाँ सुना है ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर ने अगले हफ्ते का काम एनाउन्स किया है कि उम में फना फना विज़नेस होगा। आप कह सकते हैं कि उम में बिहार पर भी डिमकशन हो। लेकिन अगर इस मौके का फायदा उठा कर बिहार पर डिमकशन करने लग जायें, तो बनती हो सकता है। मेरे पास जो मोशन आये हैं, वे ठीक नहीं हैं। अगर उन को और ढंग से लाया जायेगा, तो देखेंगे। लेकिन अगर आप चाहे कि इस मौके का फायदा उठा कर बिहार पर डिमकशन किया जाये, तो वह नहीं हो सकता है। यह आज तक नहीं हुआ है। एक इन्फोर्मेड

से आइटम को ले कर आप बिहार पर डिमकशन चलाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि अगले हफ्ते फना रेज़ोल्यूशन को भी लिया जाये। लेकिन उम के बजाय आप अभी उम पर डिमकशन करना चाहते हैं।

श्री मधु लिमये : मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री बिहार के गवर्नर और राष्ट्रपति, दोनों, से सम्पर्क स्थापित करके, बिहार में जो सांविधानिक स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उसमें बिहार सरकार का इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, उस पर सदन में बयान दे और उस पर बहस करने का मौका मिले : यह तो मैं कह ही सकता हूँ (व्यवधान)...

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) :
अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ : यह ठीक है कि श्री मधु लिमये बिहार से चुन कर आये हैं, (व्यवधान) लेकिन बिहार से जिन का रोजी-रोटी, जीवन-मरण तथा शान्ति और अशान्ति का सम्बन्ध है, वह हम लोगों का है। उनका सम्बन्ध तो केवल चुन कर आने के लिये है।

अध्यक्ष महोदय : उनका बिहार से सम्बन्ध क्यों नहीं है ? बिहार के लोगों ने उनको चुन कर भेजा है। बिहार से उनका सम्बन्ध क्यों नहीं है ?

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये और उसके बाद अपनी रूलिंग दीजिये

आपने माननीय सदस्य की बात सुनी है : उसमें बिहार का जिक्र आया है। बिहार में जो हुआ है, जो होता है और जो होगा, उससे हम लोगों का भी बहुत सम्बन्ध है : मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने किसी भी रूप में जो प्रश्न उपस्थित

[श्री शंकर दयाल सिंह]

बि या है, उसका औचित्य यहां पर है या नहीं।

मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जब मौका आयेगा, तब मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री शंकर दयाल सिंह : तो आप अपने रूलिंग को रिजर्व रख रहे हैं।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA

One naturally expects that all the items on which discussion was held inclusively would be included by the Minister. Two such items which should have been included as a matter of course are the discussion on the time capsule and the discussion on the FCI. Now, apart from that the three discussions which we have demanded and which do not find any place in the business for the next week are the following. One is the propriety of Shri B. D. Jetty continuing as the Governor of Orissa after the remarks of the High Court of Orissa. The second is the discussion on the legality of the existence of the UP Assembly after it has failed to meet for six months in terms of article 174 of the Constitution. Thirdly, a full discussion on the Draft Plan must take place before the Plan is committed to the care of the various committees which are sought to be constituted under your guidance. That must take place. If the Government could persuade itself to hold a special session of Parliament only to consider the Fifth Five Year Plan, that will probably, be justified. If that is not possible, then a full discussion should take place during the next week.

About the international situation, the Minister said that the discussion is going to take place during the next week. But we do not find any motion having been given by the Minister.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: It has been circulated.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North—East): Sir, I wish to support the idea that the discussion on the "Time Capsule" which has been buried many fathoms deep might not be buried here also. The discussion has started. It has to be completed. Otherwise, there is no point in that...

MR. SPEAKER: May I suggest, about "Time Capsule", this has already gone down and we can have the discussion any time? If it had been kept pending up to the surface, it would have been a different thing then.

SHRI H. N. MUKERJEE: If exhumation is decided upon, it is better we do it before all kinds of rotting processes take place. Putrescence must not set in. For that reason, we should discuss it. Besides that, there should be some seriousness about it. Any Parliamentary discussion or a matter taken hold of by this House should not be pushed over too long.

About the Fifth Plan discussion also, as a private Member, I have a peculiar feeling. These days, the things are promised and then something happens in the room behind your Chair, perhaps, and the decisions are taken over the head of the House....

MR. SPEAKER: There is no room behind my Chair.

SHRI H. N. MUKERJEE: There must be. Otherwise, it would have been visible.

MR. SPEAKER: Nobody can take decisions like that.

SHRI H. N. MUKERJEE: Something happens behind the scene. Now, we are told at the fag-end of the session that the discussion on the Fifth Plan is postponed. The discussion started in the last session and promised to be resumed towards the end of this session is given a cold shoulder. It is put in a cold storage somewhere. This is a very peculiar way of

behaving. But the Government is peculiar. I cannot say anything more about it.

Then, there was the Cinematograph Bill which was passed by the Rajya Sabha and placed before us for passing in the last session. It was ready for discussion and passing in the last session. It was put down on the agenda from week to week. Even the Minister happened to tell me that it was going to be taken up because he was serious about it. This is a Bill passed by the Rajya Sabha about three months ago and put before this House 2½ months ago. It was put on the Order Paper from week to week and nothing happened. I do not know why.

Again, the Bihar issue is an important one. As you have already indicated, you will consider the propriety of it; it has to be re-formulated, a kind of motion, and, as you have suggested, there are other ways of formulating it....

MR. SPEAKER: What I said was, "What you ask in one way, I reject it. If you ask in another way next week, I will see."

SHRI H. N. MUKERJEE: I would suggest to the Government, in view of the overriding constitutional issues involved, this House should have some time provided to it. This is a very serious issue. The Minister should examine it.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, firstly, I join Shri Madhu Limaye in suggesting that Bihar issue should be discussed in the House.

Secondly, I would suggest that since a serious situation has developed in the Bank of Baroda as a result of crisis in the Clearing House, as a result of cheques worth Rs. 1.25 crores and also instruments of collection remaining uncleared, a categorical statement should come—I do not say that there should be a discussion—from the Finance Minister.

2725 LS.—9.

Lastly, the Sugar Commission's Report is very important and I suggest that a discussion should be held on it. Also, the Indo-Soviet Agreement is very important and there should be a discussion on it.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Regarding the next week's business, I want to suggest that the House should discuss the communal riots that are taking place in Meerut, Allahabad and other places of U.P. Everything is discussed in the papers and government authorities are coming forward with statements. I do not know whether the Heavens will fall down if this matter is fully discussed in this House. That will rather help to pacify the situation. So, this matter should be discussed at the earliest.

The next point that I want to raise is this. Today the Reserve Bank employees are agitating over a new procedure which is going to be adopted by the Government. The Industrial Development Bank and the Unit Trust are going to be separated from the jurisdiction of the Reserve Bank. The employees have already represented I do not know what is actually in the mind of the Government. So, there must be a statement from the Finance Minister on this and it should be discussed in this House.

The next point is about reopening of Martin Burn Railway. I want a categorical answer to this. It would have been better if the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, had been here. She had assured the West Bengal people that the Martin Burn Railway would be reopened if the Congress came to power. Now the Congress is in power there. First of all, they said that the survey was going on. The survey is already complete. Now they say, that if 50 per cent of the cost is borne by the State Government, then the Central Government may take up the matter of restarting the Martin Burn Railway. This is nothing but a stunt. The West Bengal Government will never be in

[Shri Dinen Bhattacharyya]

a position to bear 50 per cent of the cost of that. So my humble submission to the Prime Minister is that she may come here and make a statement as to what will take place to the Martin Burn Railway about which she spoke so much before the elections; she must come before the House and clarify the position.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझको भी इस पर बोलने का अधिकार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खाद्य निगम के बारे में चर्चा अधूरी रह गई है वह अगले सप्ताह में पूरी नहीं होगी तो कब होगी? अगर हम अभी उस पर चर्चा नहीं करते तो आगे फिर कब करेंगे? इस तरह से चर्चा छोड़ने का मतलब क्या होगा? उसको क्यों नहीं लिया, यह तो कम से कम बता सकते हैं।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): I have already given three points on which I want to make certain suggestions.

Regarding the time capsule, already a reference has been made by Shri H. N. Mukerjee and Shri Shyamnandan Mishra. On 7th December when the discussion was initiated by me, the Minister of Education said that he would be away from 10th to 14th and, therefore, he wanted postponement of the discussion. That means, on 17th or 18th, we should have that discussion. It was a discussion under rule 193 and the time so far taken is only one hour. Now, Sir, I want to know whether, in the next week, on 17th or 18th, we would take up this discussion.

In this connection I want to make one submission. I had laid on the Table of the House the text authenticated by me and it has been accepted and published in the Bulletin. Now a good number of hon. members want to have copies of that. Do you want

me, Sir, to prepare it at my cost and distribute it to the members? The Government could arrange to circulate this. What is the harm? There are demands from many members for copies. Government has got the machinery. They can have this cyclo-styed and circulate to the members. Do you want such things to be done by the individual members?

Regarding the draft report of the Fifth Plan, as hon. members have rightly pointed out, this has been getting postponed; not only this plan but even in respect of the Third Plan and Fourth Plan also, the same thing happened. Now we have received the memorandum from your Secretariat—this was received last night and they want us to give our reaction to it to-day itself. It will be very difficult because there are very many points to be clarified... (Interruptions). We will give it tomorrow. Here, Sir, I want to know whether these committees have to function during the inter-session period, whether they will submit their reports by the beginning of the next Session, what are the facilities they are going to give and all these things.

The third thing is, as Mr. Mishra has already pointed out, the strictures on the Orissa Government and the conduct of the government there. That also merits a discussion here.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, बिहार में जो संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर यहां बहस करवायें। होना तो यह चाहिये था कि वहां की सरकार इस्तीफा देती ...

एक माननीय सदस्य : कुछ संकट ही नहीं है, तो इस्तीफा क्यों दे।

श्री रामावतार शास्त्री : उस पर यहां बहस होनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि सरकार बतलाये कि वहां की क्या स्थिति है। कम से कम सरकार से एक बयान जरूर दिलवाइये।

दूसरा—बिहार के कई जिलों में, जिनमें मुंगेर और पटना जिले भी शामिल हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नदी के कटाव से गांव कटते जा रहे हैं और लोग गृह विहीन होकर हजारों की तादाद में इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे क्षेत्र के मनर विधान सभा क्षेत्र में 15-20 वर्ष के अन्दर एक दर्जन गांव कट चुके हैं, पांच हजार लोग गृह विहीन हो चुके हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप तो बिहार का भी वक्त लेते हैं और पंजाब का भी साथ ले जाते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सारा टाइम बंगाल और बिहार ले जाता है, और भी बहुत सी बातें हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : एक दर्जन गांव कट चुके हैं, 10 करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है, 5 हजार लोग गृह विहीन हैं, अब फिर एक दर्जन गांवों के लिये खतरा उपस्थित है, उनको बचाने और बसाने पर डेढ़ करोड़ खर्चा लगेगा। बिहार सरकार कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस सिलसिले में बिजली और सिंचाई मंत्री यहां पर एक बयान दे कि पूरे बिहार और मनर क्षेत्र के कटाव की क्या स्थिति है, पीड़ितों की कठिनाई क्या है, बिहार सरकार की कठिनाई क्या है, ताकि कुछ रास्ता निकल सके, क्योंकि अब फिर 20 करोड़ रुपये की क्षति होगी और एक दर्जन से ज्यादा गांव मंगा के पेट में चले जायेंगे, तब फिर इन लोगों को कहाँ रखेंगे ?

इसलिये आपसे अनुरोध है कि इनसे बयान दिलाये और बिहार सरकार की मदद करावाये।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Although it is unnecessary for me to add to what has already been said on the floor of the House, the constitutional issue involved in the defeat of the Ministry of Bihar should be discussed in a proper constitutional forum which can be only this House, and, to enable that, the hon. Minister should make a statement thereof. I cannot overemphasize that this is a very important constitutional matter and had it happened either in Tamil Nadu or in Goa, immediately, the Congress Members or even the Government themselves would have come out with a statement creating more constitutional crisis there.

The second point that I want to raise and I want to draw your attention to is that there is a report about the discovery of oil deposits in the Kachativu island. This is a very important point. I want to draw your attention and the attention of the Government to this matter because the ownership of this island is still under dispute. Is it not an important issue, Sir? A very large quantity of oil possibility is there. The island is a bone of contention between two neighbouring States and I want to draw the attention so that the Government could come out with a statement as to what is the position there.....

MR. SPEAKER: Kindly finish. This is not going to be a debate.

SHRI SAMAR GUHA: I do not mean a debate. But what is the position? The Government should let us know.

The last point that I want to draw your attention to is: I want to know the thinking of the Government in regard to the price pattern of different newspapers. In different parts of the country the prices of newspapers have been increased unilaterally and I want to know whether Government would make a statement whether there is any uniform policy with regard to prices of newspapers. Or can they raise the price of newspapers as they

[Shri Samar Guha]

like? I want this to be made clear. Is there any uniform policy with regard to increase in the price of newspapers?

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I well realise that the week commencing on 17th December is the last week of the present session and there is pressure on time.

But, I must invite the attention of the Minister of Parliamentary Affairs to some of the outstanding issues on which discussion is absolutely essential.

We all know that the Loco Running Staff of the Railways and other Railway employees have been agitating and 'working to rule' and even striking work all over the place. This has resulted in serious dislocation of rail traffic. Number of railways have been cancelled. There is also a threat that there will be an indefinite strike from 27th February next year, as reported in UNI and PTI news-item, to press their demands. Before we adjourn for this inter-session I would like the hon. Minister for Railways to tell us in detail as to what is the Government's thinking with regard to the Railway's working. Otherwise there will be not only dislocation of traffic but also serious disturbance to the economy. So I want a full fledged assurance from the Government.

Then, Sir, continued shortage of wagons in the Western Railway Zone has resulted in sporadic crisis and erratic supply of coal to industries. Whether it is Ahmedabad or South Gujarat or Sourashtra, all over the place....

AN HON. MEMBER: Also other States....

SHRI P. G. MAVALANKAR:and other States also, this is the position. Wagons are in short supply. I hope the hon. Deputy Railway Minister is listening to me. It is a very important matter. Workers are in difficulties. Consumers are indirectly hit. I

want that, before the House adjourns this week, the hon. Minister should tell us about the Government's actual policy with regard to these matters so that this dislocation will not expand.

Then, Sir, about Five-year Plan, you will realise, during last session this matter of the Five-year Plan Approach Document came up. We all prepared the speeches and we got ready. But the debate was inconclusive. We were promised....

MR. SPEAKER: Your time is up. Please conclude.

SHRI P. G. MAVALANKAR: I am sorry. All the other hon. Members take so much time and just at the tag end we are being asked to sit down. I am not wasting even one minute than what is absolutely essential.

Then, Sir, I want to suggest that Five-year Plan is very important. We are spending the time of this national forum for so many minor details but we are not given the opportunity of discussing the basic plan document which affects the lives of millions of people in this country. That debate was inconclusive last time and this time also it continues to remain so inconclusive. Are we to be converted into a type of class-room students so that Government wants us to be members of various committees to discuss the Fifth Plan in committees and not in the House where only it becomes a national debate, public debate? I want therefore, Planning, to be taken up as an important debate next week.

Then, Sir, about UPSC report, it was brought again and again during the current session and the Minister has been assuring us, "next week", "next week.". And now this next week is the final week. Still UPSC report is not discussed.

Then, Sir, we also want the Orissa High Court judgment with regard to the misconduct of the Governor, and if copies are not available how can we

discuss the conduct of the Governor of Orissa?

On all these matters we should have discussion, and finally.. (Interruptions) One final remark. This morning I received a letter from the Pensioners.

MR. SPEAKER: Mr. Mavalankar, there should be some limit to the time. You can say one item or two items. What about the time? You are adding one after another saying one more, one more.

SHRI P. G. MAVALANKAR: No, Sir, all people who have preceded me have spoken on more than one point.

MR. SPEAKER: The hon. Member here spoke on one; the other hon. Member there spoke on two items.

SHRI P. G. MAVALANKAR: With regard to the lot of the pensioners I want the Minister of Finance to tell us as to what is the lot of the pensioners and whether they are going to get any additional allowance.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): I would like to make a submission to the Government through you....

MR. SPEAKER: You can make that through somebody else also

SHRI K. S. CHAVDA: During the last session you were kind enough to appoint a Committee of Members of Parliament from both Houses to go through the question of pay structure for the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat. I would like to know—the House is interested in it—whether any recommendation has been made.

MR. SPEAKER: I am not standing here as the Minister to reply to your supplementaries. You better come to my Chamber. If you put me on par with the Minister, then I shall have to sit there and reply from there. Don't do it. I shall take the Members into confidence.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Yesterday you said as regards P.L. 480 agreement, that you will find out from Government whether some time would be found for discussion. I want to draw your kind attention to the matter which is of vital importance to us

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना)
अध्यक्ष महोदय, मझे एक बात कहनी है..

अध्यक्ष महोदय : जब भी आपका होता है मैं आपको जरूर बुला लेता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने चिट्ठी दी है ।

अध्यक्ष महोदय : कब दी है चिट्ठी, मुझे बताइये ? ... मुझे क्यों मिसलीड करते हैं, 11 बजे के बाद दी है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारी गाड़ी चार घंटे लेट हो गई थी ।

मुझे केवल एक ही बात कहनी है । मंत्री जी ने जो कार्यक्रम रखा है उसमें शेड्यूल्ड कास्टस शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं है । हर प्रान्त में इन पर बलात्कार किये जा रहे हैं, उनको जिन्दा जलया जा रहा है और तरह तरह से अत्याचार उन पर किये जा रहे हैं । इसलिए मेरा कहना है कि सेशन समाप्त होने वाला है, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि अभी इतने सार कार्यक्रम बाकी हैं तो क्या संसद कार्य मंत्री सदन का समय बढ़ाने का विचार रखते हैं ?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: First of all, I would like to express my gratitude....

MR. SPEAKER: Gratitude for what?

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Gratitude for some of the valuable points which are so well taken up by the hon. Members.

[Shri K. Raghu Ramaiah]

First of all, about the discussion on international situation, my recollection is that a notice has been given for a motion by the Foreign Minister—I am subject to correction—and we shall certainly put it down for a discussion after the passage of the Constitution (Amendment) Bill which is scheduled for the 18th.

Regarding Fifth Five Year Plan, I have often mentioned in this House—I did mention more than once before the B.A.C. that when the draft Five Year Plan itself is ready, whether it would serve any purpose to further discuss the Approach Document. In the B.A.C., my hon. friend Shri Mishra suggested that we should follow the previous practice in this case also and the whole House in Committees should go into it. That does not bar the House from discussing it at a later stage.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: First the whole Plan is to be discussed and then that is referred to the Committees. Why this time there is this departure.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Due to shortage of time we have accepted your suggestion. Really speaking, you should be glad that we have accepted your suggestion.

Regarding unfinished discussions, I shall strain every nerve to find some time wherein I shall seek the cooperation of all the hon. Members. Subject to the international situation being discussed, Constitution (Amendment) Bill being passed and other financial matters of Government being passed, I shall strain every nerve to find time.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: How can we go without an assurance that the whole of the discussion would be taken up during the next week.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: I would only request you to kindly extend your cooperation in this re-

gard. Shri Mishra may sit with me whether he can find some time.

अध्यक्ष महोदय : अगले हफ्ते तक काम लेना है और उसके बाद टाइम भी नहीं है। अगली विजनेस एंडवाइजरी कमेटी में देखेंगे कि कौन सा विजनेस कहाँ फिट होता है, कहाँ जाता है, आगे फिर महीने डेढ़ महीने अपनी नर्व्स का ठीक करके बजट सेशन में आ जाइये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मने कल एल्काक एशडाउन का मामला उठाया था तो आपने कहा था कि सर्माचत नोटिस होनी चाहिये। अब पूरा एक दिन हो गया है लेकिन सदन के सामने कोई बयान नहीं आया है। आप कहते हैं लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ही नहीं सुनते हैं, श्रीों को क्या सुनाऊं।

श्री मधु लिमये : आप कहते हैं कि बयान देना चाहिये लेकिन वे देने नहीं हैं।

MR. SPEAKER: Hon. Members have already taken one hour more. Private Members' business will start after lunch, after the introduction of the Bills. If hon. Members are not going to take much time over it, I can take it up just now.

There are some Bills to be formally introduced. Shri Limaye had said that he wanted to oppose the introduction.....

PROF. MADHU DANDAVATE: We just want to mention the grounds for the opposition.

SHRI SEZHIYAN: In regard to item No. 14 I have already written to you that I am going to oppose the introduction of the Bill.

MR. SPEAKER: That was to be done before the lunch hour. It is

already nearing 2 p.m. Immediately after lunch hour, items Nos. 12 to 16 relating to formal introduction of Bills will be disposed of, and Private Members' business will be postponed to that extent. In my opinion it would not take more than half an hour. If hon. Members like, we may not go for lunch but we may continue...

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. SPEAKER: We now adjourn for lunch till 3 p.m.

13.57 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

SHRI MOHAMMAD ISMAIL (Barackpore): I want to mention one thing for your information. This is a telegram which I have received from my constituency:

"Kailash Chowbey Texmaco Workers Union leader seriously stabbed last night in residence by Congressite goondas stop Rowdies threatening our members stop Police not arresting culprits stop Situation grave stop Request intervention stop"

Trade union workers have been stabbed in their residence. The police do not intervene. I want to make this submission...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, order. Let us get on with the business.

A number of Bills are to be introduced. Some hon. members have given notice that they would oppose the introduction of these Bills. In this connection, I would say that generally there are two grounds on

which introduction of a Bill can be opposed. First, that the Bill is outside the legislative competence of this House, and second, that there are procedural obstacles. Merits of the Bill are not matters for opposing introduction.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Also demerits.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Demerits and merits are not matters for opposing introduction; they are matters for discussion. I would like hon. members to keep this in mind when they make their submissions.

15.05 hrs.

**KONKAN PASSENGER SHIPS
(ACQUISITION)* BILL**

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLA-PATI TRIPATHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the Konkan passenger ships in order to serve better the needs of the maritime passengers of the Konkan coastal region and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquisition and transfer of the Konkan passenger ships in order to serve better the needs of the maritime passengers of the Konkan coastal region and for matters connected therewith or incidental thereto".

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): After noting your observation, I will only try to point out to you what are the procedural difficulties on the basis of which I am actually opposing the introduction of